



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269763
CG-DL-E-02022026-269763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 435]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 464(अ.).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 5320(अ) तारीख 21 नवंबर, 2025 द्वारा, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संहिता” कहा गया है) के सभी उपबंध 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त किए गए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त संहिता की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 5683(अ) तारीख 8 दिसंबर, 2025 का आंशिक उपांतरण करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता (कठिनाइयों का निवारण) (संशोधन) आदेश, 2026 है।

2. औद्योगिक संबंध संहिता (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2025 में दूसरे पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3. यह और स्पष्ट किया जाता है कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16), औद्योगिक नियोजन [स्थायी आदेश] अधिनियम, 1946 (1946 का 20) और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन सभी विद्यमान कानूनी प्राधिकारी कृत्यों की निरंतरता, निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने और किसी विधिक या प्रशासनिक अंतराल से बचने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन ऐसे कानूनी प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाने तक कार्य करते रहेंगे।”

[फा.सं. एस-11025/07/2025-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 464(E).—WHEREAS *vide* notification number S.O. 5320(E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), all the provisions of the Industrial Relations Code, 2020 (hereinafter referred to as “the Code”) have been brought into force with effect from the 21st day of November, 2025;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 103 of the said Code and in partial modification of the notification number S.O. 5683(E), dated the 8th December, 2025, the Central Government hereby makes the following amendments in the said Order, namely:—

1. This Order may be called the Industrial Relations Code (Removal of Difficulties) (Amendment) Order, 2026.

2. In the Industrial Relations Code (Removal of Difficulties) Order, 2025, after the second paragraph, the following shall be inserted, namely:—

“3. It is further clarified that all the existing statutory authorities under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926), the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946) and the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall continue to function until the appointment of such statutory authorities under the Industrial Relations Code, 2020 for ensuring continuity of functions, smooth transition and avoiding any legal or administrative vacuum.”.

[F. No. S-11025/07/2025-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.